(ख) यदि हां, तो क्या दल ने सभी पहलुओं पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) भारत सरकार ने लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों व प्रौद्योगिकी के चयन के बारे में सिफारिश करने हेतु क्रमश दो कार्यकारी दलों का गठन किया है। वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है । प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट का शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। सरकार दोनों रिपोर्टों पर विचार करेगी और यथाशीघ्र उन पर उपयुक्त निर्णय लेगी।

Demand and Production of Paper

*358 SHRI A R BADRI NARAYAN Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) the total requirement of paper of all categories in the country,

(b) the total overall production in the several factories, public and private and

(c) how is the shortfall proposed to be made up?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) (a) The total requirement of all categories of paper is estimated to be aobut 8 50 lakh tonnes for 1978-79

(b) The overall total production of all categories of Paper in the country has been 7 88 lakh tonnes during 1977 of which 7 54 lakhs tonnes has been in Private Sector and 0 34 lakh tonnes in Public Sector

(c) Additional capacity is being set up in the Public and Private Sectors to increase the production of common varieties of Writing and Printing Papers Government have also allowed the facility of import of second hand equipment for small paper mills. These steps are expected to result in continuos growth of capacity to enable production to keep pace with future demand If found necessary, Government will also import common varieties of writing and printing paper

कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से करार

*359 श्री राम सेवक हजारी :
श्री बहुलद एम० पटेल

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच संयुक्त कोयला गैसीकरण परियोजना आरम्भ करने के बारे में कोई करार हुआ है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं , और

(ग) इससे कोयले के उचित उपयोग में कितनी सहायता मिलेगी और परिणामस्वरूप उसके प्रयोग में कितनी कमी होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच हुई अनेक बैठकों के परिणामस्वरूप, जिनमें बी०एच०ई०एल० के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था, भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कोयला गैसीकरण की एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एक करार किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक विकासशील देश द्वारा किया गया यह पहला करार है ।

भारत की ओर से बी०एच०ई०एल० को उनकी चालू अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं, कोयला गैसीकरण और इस क्षेत्र में अन्तर्ग्रस्तता को ध्यान में रखते हुए परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है । एक उपयुक्त गैसीकरण प्रक्रिया का विकास करने में बी०एच०ई०एल० का उद्देश्य इसे विकसित विद्युत कार्यक्रमों (साइकल्स) में लागू करने का है, जिसकी कार्यकुशलता अधिक है और इससे पूंजी लागत भी कम होती है । इससे पेट्रोलियम ईंधनों, जिनका उपयोग औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों में होता है, के स्थान पर कोयला गैस का प्रयोग किया जा सकेगा । कोयला-गैसीकरण के संबंध में संयुक्त अध्ययन बी०एच०ई०एल०, भारत और नेशनल कोल बोर्ड, ग्रेट ब्रिटेन और वर्गबाऊ फोर्सचुंग, जी०एम०बी०एच०, पश्चिम जर्मनी, जो कमीशन आफ यूरोपियन कम्युनिटीज के परामर्शदाता हैं, के विशेषज्ञों द्वारा किया जायगा। बी०एच०ई० एल० और दो सहभागी संगठनों के बीच एक संयुक्त कार्य